संख्या-11 /2018/368/पचासी-2018-67(परती)/2017

प्रेषक,

टी. वेंकटेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ: दिनांक:: 27 अप्रैल, 2018

विषय:- उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-।।। (विश्व बैंक पोषित) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम 06 माह (अप्रैल से सितम्बर, 2018) के व्यय के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्रांक-3बी/01/बजट/2018-19/01, दिनांक-02 अप्रैल, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-।।।(विश्व बैंक पोषित) योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 13000.00 लाख (रूपये एक अरब तीस करोड़ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 6500.00 लाख (रूपये पैंसठ करोड़ मात्र)** व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि के आहरण हेतु बिल उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के बाद सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का यथावश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा।

3- धनराशि के उपयोग का अनुश्रवण सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जो इसके एकाउण्टस भी तैयार कराकर ससमय उपलब्ध करायेंगे।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

5- उक्त धनराशि का उपयोग योजना की विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना तथा कार्ययोजना के अनुरूप विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद मे इसका डायवर्जन किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा रिट्रोएक्टिव फाइनेन्सिंग के अन्तर्गत धन देने के लिए सहमति दी गयी है।

6- उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट असेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9704-उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट -।।। (विश्व बैंक पोषित) के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/10-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 दवारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10- उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30 मार्च, 2018 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(टी. वेंकटेश)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रमुख सचिव।

संख्या-**11** /2018/368/पचासी-2018-67(परती)/2017-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालत्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-1
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अनीता वर्मा सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।